enabling import of capital goods at concessional duty for export production, special arrangements for duty free import of raw materials for export production, etc.

वस्त्र मंत्रालय का वार्षिक योजनागत परिव्यय

920. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला**: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने वर्ष 1998-99 के लिए वस्त्र मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं हेतु कुल कितना वार्षिक परिव्यय स्वीकृत किया हैं;

(ख) इसके अंतर्गत वस्त्र उत्पादन एंव निर्यात की अपेक्षित दरें क्या-क्या हैं;

(ग) मंत्रालय ने उपर्युक्त कुल परिव्यय के अंतर्गत महाराष्ट्र और गुजरात के लिए कितना वित्तीय प्रावधान रखा हैं;

(घ) उक्त वर्ष में इन राज्यों की अनुमोदित की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या हैं;और

(ड़) इसके अंतर्गत क्या-क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) वर्ष 1998-99 में वस्त्र मंत्रालय के लिए वार्षिक योजना परिव्यय 240.88 करोड़ रू. हैं ।

(ख) वर्ष 1998-99 में यार्न और फैब्रिक का उत्पादन तथा वस्त्रों के निर्यात मूल्य पिछले वर्ष के स्तर पर बने रहने की संभावना हैं ।

(ग) मंत्रालय के लिए योजना स्कीम वस्त्र उद्योग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाई जाती है और राज्य-वार आरक्षण नहीं किया जाता हैं ।

(घ) और (ड़) वर्ष 1998-99 के लिए महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में चालू योजनाओं की सूची संलग्न विवरण में निर्दिष्ट हैं।

विवरण

योजनाओं के नाम	महाराष्ट्र	गुजरात
विद्युतकरघा:		
(क) विद्युतकरघा सेवा केन्द्र	प्रचालन में	प्रचालन में
(ख) कम्प्यूटर सहायित डिजाईन केन्द्र	-वहीं-	-वहीं-
(ग) विद्युतकरघा बुनकरों के लिए बीमा योजना	-वहीं-	-वहीं
हथकरघा:		
(क) प्रचार एंव प्रदर्शनी	शून्य	प्रचालन में
(ख) बचत निधि योजना	-वहीं-	-वहीं-
(ग) कार्यगृह-सह-आवास	-वहीं-	-वहीं-
(घ) परियोजना पैकेज	प्रचालन में	-वहीं-
(ड़) बाजार विकास सहायता	-वहीं-	-वहीं-
हस्तशिल्प:		
(क) प्रदर्शनी एंव प्रचार	प्रचालन में	प्रचालन में
(ख) प्रशिक्षण	-वहीं-	-वहीं-
(ग) सर्वेक्षण और अध्ययन	-वहीं-	शून्य
(घ) इम्पोरियम का नवीकरण	शून्य	प्रचालन में

योजनाओं के नाम	महाराष्ट्र	गुजरात
(ड़) डिजाईन विकास	प्रचालन में	-वहीं-
(च)बाजार विकास	-वहीं-	-वहीं-
रेशम उत्पादन:		
(क) राज्यों को विभिन्न प्रकार के शहतूती बैकों में सुधार	प्रचालन में	प्रचालन में
(ख) ऑन-फार्म प्रशिक्षण देने तथा औज़ारों की आपूर्ति करने के लिए राज्यों को सहायता	-वहीं-	शून्य
(ग) विस्तार और प्रचार सामग्री तैयार करने के लिए सहायता	-वहीं-	-वहीं-
(घ) राज्यों को मास्टर रीलर सहायता	-वहीं-	-वहीं-
ऊन:		
(क) एकीकृत भेड़ व ऊन विकास परियोजना	शून्य	प्रचालन में
(ख) मशीन कतरन-सह-प्रशिक्षण परियोजना	-वहीं-	-वहीं-

Garment Quota Entitlement

921. SHRI SITARAM KESRI: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether under pressure from the European Union over the recent controversy on overshooting the 1998 garment quota entitlement, India has agreed to bind import duties on a wide array of textile sector items with the World Trade Organisation; and

(b) if so, what are the details thereof and the reasons therefor?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI KASHIRAM RANA): (a) and (b) No, Sir. In the Indo-EU-MOU on market access for textiles and clothing products signed on 31.12.1994, which provided mutual benefits, Government had agreed, inter-alia, to reduce its import tariffs and bind its tariffs by notifying to the WTO in respect of the textile items listed in the MOU. Different textile products, including fibres, yarn, fabrics, made-ups and garments, and totalling 220 HS lines, are covered under the MOU.

राष्ट्रीय परिधान निर्यात नीति

922. **श्री गोविन्दराम मिरी**: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार ने कोई राष्ट्रीय परिधान निर्यात नीति बनायी हैं;

(ख) यदि हां,तो इसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) विगत पांच वर्षो के दौरान उपरोक्त नीति को किन-किन पहलुओं के संबंध में कार्यान्वित किया गया हैं;

(घ) क्या कार्यान्वयन में किन्हीं बाधाओं का सामना करना पड़ा है;और

(ड़) यदि हां,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन बाधाओं को दूर करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) से (ड़) परिधानों को,यूरोपीय संघ के सदस्य देशों,यू.एस.ए.और कनाडा जो द्विपक्षीय करारों के अनुसार मात्रात्मक प्रतिबंधों के अंतर्गत हैं,निर्यात के संबंध में